भारत की पहली डिजीटल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ

सवेरा न्यूज/रविंदर शर्मा

जालंधर, 19 जुलाई : भारत की पहली एआई-पावर्ड, आधुनिक डिजीटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के चेयरमैन उदय उमेश ललित द्वारा किया गया। ज्युपीटाईस टैक्नोलॉजीस द्वारा इस डिजीटल लोक अदालत का डिज़ाइन और अवधारणा विकसित की गई है। डिजीटल लोक अदालत का शुभारंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमाना, कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जयपुर में किया गया।

डिजीटल लोक अदालत के माध्यम से पुराने लंबित मामलों का निपटान किया जा सकेगा या ऐसे मामलों को भी आसानी से निपटाया जा सकेगा जो आरंभिक चरण में हैं। इससे विवाद निपटान की प्रक्रिया आधुनिक बनेगी, जहां आवेदन के ड्राफ्ट और फाइलिंग से लेकर एक क्लिक पर ई-नोटिस जनरेशन, स्मार्ट टैम्पलेट, ड्राफ्ट सैटलमैंट समझौता और वीडियो-कॉन्फ्रैंसिंग के ज़रिए डिजीटल सुनवाई तक सभी पहलुओं को बढ़ावा मिलेगा।

ज्युपीटाईस देश के विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थानों और एडीआर सैंटरों के साथ काम कर रही है ताकि विवादों के निपटान के लिए डिजीटल प्रणाली को अपनाया जा सके। ज्युपीटाईस ने न्याय प्रणाली की मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए गहन अनुसंधान के बाद डिजीटल लोक अदालत की अवधारणा डिजाइन और विकसित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैब, मोबाइल और सीएससी के ज़रिए देश के दूर-दराज के इलाकों तक भी न्याय पहुंचे तथा अन्य सेवाओं की तरह न्याय को किफायती बनाया जा सके।